नियुक्ति करना

61. श्री नरेन्द्र कुमार नीरज--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना के कंकड़बाग स्थित विकलांग भवन में राज्य सरकार द्वारा बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी/अकुपेशनल थेरेपी संचालित है जिसमें फिजियोथेरेपी चिकित्सा एवं उससे संबंधित विषयों की पढ़ाई होती है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कॉलेज में शैक्षणिक पदों पर एक भी फिजियोथेरेपी/अकुपेशनल थेरेपी में पी०जी० डिग्रीधारी शिक्षक नहीं है जबकि यह डिग्री अनिवार्य है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कॉलेज में निर्धारित मापदंड के अनुसार पी०जी० डिग्रीधारी फिजियोथेरेपिस्ट/अकुपेशनल थेरेपिस्ट की नियुक्ति शैक्षणिक पदों पर करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विन्डो सिस्टम लागू करना

62. श्री नितिन नवीन--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विकलांगों को विकलांगता सर्टिफिकेट मेडिकल बोर्ड द्वारा दिया जाता है;

(2) क्या यह बात सही है कि मेडिकल बोर्ड की नियमित बैठकें नहीं होने के कारण असहाय विकलांगों को सदर अस्पताल बार-बार दौरना पड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विकलांगता सर्टिफिकेट निर्गत करने हेतु प्रत्येक जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर विंडो सिस्टम लागू करने तथा सभी कार्य दिवसों में उसे कार्यरत रखने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पत्र को लागू करना

63. श्री संजय सरावगी--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती होने वाले सभी मरीजों को पत्रांक 737, (12), दिनांक 24 अगस्त, 2010 के अनुसार सभी जांच पैथोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल (बी०पी०एल० परिवारों को सी०टी० स्कैन एवं एम०आर०आई० सहित एवं ए०पी०एल० परिवारों को सी०टी० स्कैन एवं एम०आर०आई० छोड़कर) निःशुल्क करने का निर्णय लिया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि इसका अनुपालन दरभंगा समेत किसी भी मेडिकल कॉलेज में नहीं हो रहा है;

(3) यदि उपर्युकत खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (1) में वर्णित पत्र को लागू करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उच्चस्तरीय जांच कराना

64. डॉ० अच्युतानन्द--दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 9 जनवरी, 2011 के अंक में छपी खबर "दवा खरीद में करोड़ों का गोलमाल" के आलोक में क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य स्वास्थ्य समिति ने बगैर निविदा निकाले तीन करोड़ रुपये की आयुष चिकित्सा हेतु दवा वर्ष 2009-10 में ऐसी कम्पनी से खरीदी गयी जिसे जी०एम०पी० प्राप्त नहीं था;

(2) यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त दवा खरीद में की गई गड़बड़ी की उच्च स्तरीय जांच कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जान्वित करना

65. श्री ई० अजीत कुमार--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि 8 फरवरी, 2010 को राज्य में फेज 11 के तहत लगे 2700 नलकूप को चालू करने के लिए विद्युत विभाग एवं लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री व अधिकारी स्तर पर वार्ता हुई थी;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त बैठक में दोनों विभागों द्वारा संयुक्त रूप से निर्णय लिया गया था कि तीन माह के अन्दर प्रथम चरण में 600 नलकूप को ऊर्जान्वित किया जायेगा;

(3) क्या यह बात सही है कि नलकूप पर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लघु जल संसाधन विभाग द्वारा डिपोजिट स्कीम के तहत ऊर्जा विभाग को दो वर्ष पूर्व पैसा दिया जा चुका है, फिर भी अभीतक कार्य नहीं हुआ है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त नलकूपों को ऊर्जान्वित कर चालू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

66. डॉ० इजहार अहमद---स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र दिनांक 31 जनवरी, 2011 को प्रकाशित शीर्षक "कागजों में रौशन हुए बी०पी०एल० परिवार" को ध्यान रखते हुए क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय एजेंसी पावर ग्रीड ने मुख्य मंत्री जी की विश्वास यात्रा के दौरान तिरहुत विद्युत आपूर्ति क्षेत्र में सात लाख बी०पी०एल० परिवारों को बिजली कनेक्शन देने की बात कही;

(2) क्या यह बात सही है कि बिजली बोर्ड के उच्चाधिकारी गांवों का दौरा किया तो पता चला कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत पावर ग्रीड के देख-रेख में मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली और मोतिहारी समेत अन्य जिलों को सात लाख बी०पी०एल० परिवारों को कनेक्शन दिया गया है लेकिन जब बोर्ड ने रिपोर्ट तलब किया तो मात्र 35 हजार मिला;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कनेक्शन के नाम पर खानापूर्ति रिपोर्ट बनाकर देने वाले एजेंसियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक और नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 25 मार्च, 2011 (ई०) ।

गिरीश झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा ।